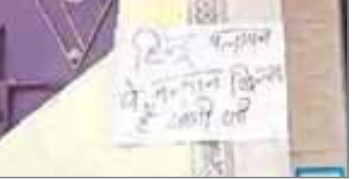


दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद तनाव

● परिजन का आरोप-कई मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में मारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे इलाके में तनाव है।



परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्काजाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। उधर, सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो।

तेलंगाना-हरियाणा के बाद आंध्र में भी आरक्षण में सब-कोटा

● अध्यादेश जारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम



अमरावती (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया। राज्य में कुल 59 एससी जातियों को 15 फीसदी आरक्षण मिलता है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी और अनुसूचित जनजातियों कोटे में कोटा देने की अनुमति दी थी। आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए एससी जातियों को तीन गुण में बांटा गया है।

धार्मिक नाम पर आवंटित वक्फ संपत्तियों पर बने हैं मकान-दुकान

● यूपी के जिलों से आने लगी रिपोर्ट, 761 से अधिक संपत्तियां हैं शामिल

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी के जिलों से जिलाधिकारियों ने धीरे-धीरे वक्फ संपत्तियों की जानकारी शासन को भेजनी शुरू कर दी है। शासन को अब तक मिली जिलों की रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक, शैक्षिक कामों



और कब्रिस्तान के लिए दी गई 761 से अधिक संपत्तियों पर घर और दुकानें बना दी गई हैं। शासन ने जिलाधिकारियों से वक्फ संपत्तियों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि वक्फ की संपत्तियों का आवंटन के बाद मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों में स्थित वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे।

अमेरिका ने खालिस्तान पर खोली आईएसआई की पोल

● एफबीआई के हथे चढ़ा बख्तर खालसा का आतंकी हथप्रिय भारत को बड़ी सफलता

वॉशिंगटन (एजेंसी)। भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार खालिस्तानी आतंकवादी हरप्रीत सिंह अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है। अमेरिकी की संघीय जांच एजेंसी ने हरप्रीत को सैक्रामेंटो में गिरफ्तार किया। एफबीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसे भारत में लीगल अटैचे कार्यालय के एजेंटों ने सूचना दी थी कि हरप्रीत सिंह पंजाब, भारत में कई आतंकी हमलों के सिलसिले में वांछित था। दिलचस्प बात है कि हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही अमेरिकी जांच एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से खालिस्तानियों के कनेक्शन की पोल भी खोल दी है। एफबीआई ने बयान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सीधा जिक्र किया है।

मुस्लिमों की ही सुनी, तब बनाया है वक्फ कानून

पीएम ने कहा- 1700 शिकायतें मिलने के बाद बना है वक्फ एक्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 सैकड़ों शिकायतों के बाद लाया गया है, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों,

● पीएम बोले-विशेष रूप से महिलाओं-विधवाओं की रही प्रमुख भूमिका

विशेष रूप से महिलाओं और विधवाओं की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने



यह बात दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें विभिन्न मुस्लिम समुदायों से वक्फ संपत्तियों को लेकर 1700 से अधिक शिकायतें मिली थीं, जिससे सरकार को इस मुद्दे पर

कई जगह वक्फ कानून को लेकर भारी विरोध

हालांकि, वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध भी देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून को मुस्लिम विरोधी कारर देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह कानून देश को बांटने वाला है और इसे लागू नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कानून का स्वागत करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों से अमीर और प्रभावशाली मुस्लिमों द्वारा किए गए अतिक्रमण को खत्म करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने विशेष रूप से वक्फ-बाग-यूजर श्रेणी को हटाने, गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए राज्य को दी गई।

अधर में लटकी कर्नाटक की जाति जनगणना

अभी जारी नहीं होंगे नतीजे, 2 मई को अगली बैठक



थी। हमने विभिन्न समुदायों की जनसंख्या, उनके पिछड़ापन और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर उठाए

गए विवाद इस चर्चा का हिस्सा नहीं थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्रियों से सर्वेक्षण पर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

गए विवाद इस चर्चा का हिस्सा नहीं थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्रियों से सर्वेक्षण पर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों ने किया विरोध

गौरतलब है कि वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों ने इस सर्वे को अवैज्ञानिक बताते हुए इसे खारिज करने और एक नया सर्वेक्षण कराने की मांग की है। पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली कैबिनेट बैठक 24 अप्रैल को एम एम हिस्स में होगी, लेकिन उस बैठक में सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की जाएगी। उस बैठक में पुराने मैसूर क्षेत्र से संबंधित मुद्दे लिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट मंत्रियों से कहा गया है कि वे सर्वेक्षण को लेकर अपनी राय लिखित रूप में 2 मई की बैठक में प्रस्तुत करें।

वाड़ा के खिलाफ तीन मामलों में ईडी की चार्जशीट तैयार

गुरुग्राम से लंदन तक मनी लॉन्ड्रिंग का खेल !

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड़ा के खिलाफ अपनी जांच को और तेज कर दिया है। ईडी जल्द ही वाड़ा के खिलाफ तीन अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। गुरुग्राम लैंड डील केस सहित इन मामलों में वाड़ा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की गई, जो कुल



वाड़ा पर 7.5 करोड़ रुपये में जमीन खरीदकर कुछ ही महीनों में उसे 58 करोड़ रुपये में बेचने का आरोप है। दूसरा मामला भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े लंदन स्थित प्रॉपर्टीज का है, जिन्हें कथित तौर पर रक्षा सौदों से मिले अवैध पैसे से खरीदा गया था।

संजय भंडारी और बीकानेर भूमि सौदा

वाड़ा पर दूसरा आरोप यूके स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ कथित संबंधों का है। ईडी पहले ही संजय भंडारी और वाड़ा के करीबी सीसी थंपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी के अनुसार, भारत द्वारा स्विस् कंपनी पिलाटस से 75 ट्रेजर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए हुई डील में 310 करोड़ रुपये की कथित घूस दुबई स्थित भंडारी की कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस एफजेडसी के खातों में गई।

‘सारंगी को बचाना है तो सारंगी की गर्द झाड़कर उसे बैठकों तक लाना होगा



भा रतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा में सारंगी वाद्य पर पुरुष कलाकारों का आधिपत्य रहा है, इसे सबसे पहले बीती सदी के सातवें दशक में ख्यात सारंगी वादक पंडित राम नारायण की पुत्री अरुणा कल्लेत ने तोड़ा था। अरुणा कल्ले बीते लगभग चार दशकों से कनाडा जा बसीं।

इस रिक्तता को समाप्त करने का बीड़ा जमशेदपुर (झारखंड) निवासी गौरी बनर्जी सती ने उठाया और आज युवा गौरी बनर्जी सती का नाम देश भर में देश की दूसरी महिला सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है । वो पिछले साल भी इस समारोह में आई थीं। तब उन्होंने समारोह की छह निशाओं में नौ कलाकारों विदुषी कंकणा बनर्जी, नंदिनी बेडेकर, मीनाक्षी मजूमदार, दिवाकर कश्यप, पंडित सीनक अभिषेकी, पंडित जयतीर्थ मेचुंडी, पंडित नीरज पारिख के साथ प्रभावशाली संगत की। संकट मोचन संगीत समारोह के 102वें आयोजन में दूसरी हाजिरी लगाने गौरी बनर्जी सती वाराणसी आई हुई हैं और इस बार पंडित अजय पोहनकर (मुंबई), रोहित पवार (दिल्ली), श्रीमती सोहन राय चौधरी (कलकत्ता) पंडित नीरज पारीख (अहमदाबाद) के साथ समारोह की प्रथम व द्वितीय निशा में प्रस्तुतति दे चुकी हैं। गौरी चौथी निशा (19 अप्रैल) को विदुषी कंकना बनर्जी के साथ संगत करेंगी।

जमशेदपुर के साकची स्थित पेनार रोड के टाटा स्टील कंपनी के क्वार्टर में रहने वाले ख्यात तबला वादक पं. किशोर बनर्जी और उनकी सितार वादक

पत्नीक तंद्रा बनर्जी के घर आंगन में जन्मीत गौरी को शास्त्रीय संगीत घुटटी में मिला है। इस मायने में वह अपने परिवार की चौथी पीढ़ी की कलाकार हैं। छोटी बच्चीर गौरी सुबह शाम अपने पिता पं. किशोर बनर्जी को तबले पर और मां तंद्रा को सितार पर रियाज करते रून वाद्यों के प्रति आकर्षित हुईं किन्तु सितार वादक उनकी मां श्रीमती तंद्रा बनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स वाद्य यंत्रों की बढ़ती मांग और सारंगी की उपेक्षा से चिंतित थीं। अपनी इस चिंता का हरण तंद्रा बनर्जी ने पांच बरस की अपनी बेटी गौरी के नन्हे हाथों में गज (सारंगी के तारों को रगड़ देने वाला उपकरण) पकड़वा कर तारों को छेड़ना सिखाया। घर पर ही अभ्यास करते करते गौरी सारंगी में खोई रहती। सारंगी हाथ में पकड़ जब घर से बाहर निकली तो 'एश मेये जनों कथा नेई' (यह सब लड़कियों के बूते का नहीं) जैसे तानों ने गौरी को सारंगी के प्रति प्रतिबद्धता से

भर दिया।और गौरी ने ठान लिया कि वह जीवन में और कुछ बने न बने, लेकिन सारंगी वादक जरूर बनेगी। गौरी बनर्जी की इस प्रतिबद्धता को परवान बनारस से निकलकर रांची जा बसे गुणी सारंगी वादक पं. काशीनाथ मिश्र व दिल्ली के दिग्गज उस्ताद सावरी खां साहब ने चढ़ाया। सारंगी के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए गौरी कहती है कि 'सारंगी को बचाना है तो ऐसे ही जतन केसाथ संगीत से जुड़े घरानों को घरों के कोने में पड़ी धूल फांक रही सारंगी की गर्द झाड़कर उसे बैठकों तक लाना होगा। 'ए' ग्रेड आर्टिस्ट्स के रूप मे स्थातपित गौरी बनर्जी दूरदर्शन व आकाशवाणी के पांच दर्जन से अधिक राष्ट्रीय संगीत समारोहों, इंदौर के प्रतिष्ठपरक संगीत उत्सव राग



आमिर, उदयपुर के महारणा संगीत कुंभ, कालिदास समारोह (गुजरात) में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। गौरी बनर्जी की सारंगी के प्रति बेपनाह मोहब्बत का नतीजा साल 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय सामने आया। जब गौरी बनर्जी को राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप व मोदी के समक्ष सारंगी वादन का मौका मिला। गौरी की सारंगी

प्रस्तुसति के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेसाखात कह उठे 'इट्स फंटास्टिक, इट्स वेल्डन।' गौरी के सारंगी वादन से मंत्रमुग्ध ट्रंप ने गौरी के साथ सेल्फी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गौरी के वादन की भूरि भूरि प्रशंसा की ।

गौरी बनर्जी सती ने सारंगी के साथ साथ अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। वे फलस्वरूप चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और हल्चौरनी के मूल निवासी उनके जीवन साथी पारितोष सती भी चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। गौरी को सबसे अधिक संतोष और खुशी अपने पिता पं. किशोर बनर्जी के साथ संगत करने में मिलती है। बाप-बेटी की इस जोड़ी नेकई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नायाब युगलबंदी से सबको मोहित किया है। सफर के दौरान सारंगी को अपने गोद में लेकर बैठना उनका शगल है। वह कहती है कि सारंगी को इतना सम्मान होगा। 'ए' ग्रेड आर्टिस्ट्स के रूप मे स्थातपित गौरी बनर्जी दूरदर्शन व आकाशवाणी के पांच दर्जन से अधिक राष्ट्रीय संगीत समारोहों, इंदौर के प्रतिष्ठपरक संगीत उत्सव राग

वर्तमान में सारंगी की उपेक्षा से दुखी गौरी बनर्जी सती कहती है कि 'आज अस्तित्व के संकट से गुजर रहा सबसे सुरीला बाजा सारंगी नई पौध को बड़ी उम्मीद से आवाज दे रहा है। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं मगर ग्लैमर और पैसे की अंधी दौड़ ने राहें बदल दी हैं। इसमें पहल संगीत घरानों की होनी चाहिए, अन्य विधाओं से कोई होड़ नहीं किंतु सारंगी कहीं खूटी पर न लटक जाए इसकी चिंता इन घरानों की जिम्मेवारी है।' उम्मीद की जानी चाहिए कि सारंगी वादक गौरी बनर्जी सती की आवाज संगीत घरानों तक पहुंचेगी ।

10,000 की भीड़ हुई जमा छीन ली पुलिस की पिस्तौल

वक्फ हिंसा पर हाईकोर्ट में ममता सरकार का कबूलनामा

कोलकाता (एजेंसी)। वक्फ संशोधन ऐक्ट के खिलाफ पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि हिंसा के दिन करीब 10,000 की भीड़ जमा हो गई थी। इतना ही नहीं उन्मादी भीड़ ने तब मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल भी छीन ली थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्मादी भीड़ में से करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे, जिनसे पुलिस को अपने अधिकारियों को बचाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपद्रवियों की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई।



रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले करीब 8000-10000 लोगों की भीड़ पीडब्ल्यूडी ग्राउंड आउट पर इकट्ठा हुई। इसके बाद भीड़ का एक हिस्सा अलग हो गया और करीब 5000 लोग उमरपुर की ओर बढ़ गए और एनएच को जाम कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगी। इसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ईट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक-एक सदस्य वाली तीन सदस्यीय समिति लोगों के पुनर्वास पर बात करे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले करीब 8000-10000 लोगों की भीड़ पीडब्ल्यूडी ग्राउंड आउट पर इकट्ठा हुई। इसके बाद भीड़ का एक हिस्सा अलग हो गया और करीब 5000 लोग उमरपुर की ओर बढ़ गए और एनएच को जाम कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगी। इसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ईट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक-एक सदस्य वाली तीन सदस्यीय समिति लोगों के पुनर्वास पर बात करे।

‘प्रसाद योजना’ से संवरेगी माँ पीताम्बरा की नगरी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि माँ पीताम्बरा की नगरी को प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनने के लिये सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की ‘प्रसाद योजना’ (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) के अंतर्गत मंदिर परिसर और उससे जुड़े क्षेत्र के विकास के लिए 44.24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना से धार्मिक स्थलों का कायाकल्प होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा। ‘प्रसाद योजना’ का उद्देश्य भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।

धार्मिक विरासत को मिलेगा आधुनिक स्वरूप- प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति और प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पीतांबरा पीठ में पर्यटन सेवाओं के विस्तार से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। सुविधाएं बढ़ने से यह विकास तीर्थयात्रियों को आसानी होगी।

सड़क किनारे लगे पेड़ों का घुट रहा दम

भोपाल (नप्र)। भोपाल में सड़क किनारे लगे पेड़ों की जड़ों को कांक्र्रीट से ढ़क दिया गया है। इसके चलते जेल रोड, व्यापम चौराहा, शिवाजी नगर जैसे कई इलाकों में लगे ये घने और छायादार पेड़ सूखने लगे हैं। दरअसल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए शहर भर में सड़क निर्माण और रिपेयरिंग का काम किया गया था। इस दौरान सड़क किनारे लगे पेड़ों के आसपास की जमीन को भी डामर से कवर कर दिया गया। इससे उनकी जड़ों तक हवा और पानी दोनों ही नहीं पहुंच पा रहा है। लम्बे समय तक यही स्थिति बनी रहने पर यह विशालकाय पेड़ सूख जाँगे।

ज्यादा समय तक अनदेखी से सूख जाएंगे पेड़- जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अशोक के मुताबिक पेड़ के लिए जड़ें सबसे जरूरी होती हैं। ये ना सिर्फ पेड़ को जमीन पर टिकाए रखती है, बल्कि पानी, हवा और जरूरी पोषक तत्व भी पहुंचाती है। पेड़ के आसपास की मिट्टी-जमीन को डामर या सीमेंट से कवर कर देने से जड़ों तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच पाती। इससे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ज्यादा समय तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने से ये सूख भी सकते हैं।

घटता जा रहा भोपाल का वनक्षेत्र- उधर, एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के अंत तक भोपाल में सिर्फ 3 प्रतिशत वन क्षेत्र बचेगा। पिछले एक दशक में भोपाल ने अपने 26 प्रतिशत वनक्षेत्र हिस्से को खो दिया है। ऐसी स्थिति में पेड़ों की जड़ों से डामर और कन्क्रीट हटना बेहद जरूरी है।

कैलाश विजयवर्गीय से प्रेरणा लें अन्य नेता : राकेश शर्मा

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री कार्यकर्ता और जनता के लाड़ले नेता कैलाश विजयवर्गीय का जन्मदिन 30 अप्रैल को है। कैलाश विजयवर्गीय को चाहने वाले कार्यकर्ता और समर्थक अभी से इंदौर शहर में होर्डिंग और पोस्टर लगाने लगे हैं, यह जब कैलाश विजयवर्गीय के संज्ञान में आया तो उन्होंने हाथ जोड़कर अपने समर्थकों और चाहने वालों से निवेदन किया कि वह होर्डिंग और पोस्टर शहर में न लगाएं क्योंकि होर्डिंग और पोस्टर से शहर भी गंद लगता है और शहर की स्वच्छता भी खराब होती है। इंदौर शहर स्वच्छता में लगातार नंबर बना रहा है, हमारा दायित्व बनता है कि इंदौर शहर की स्वच्छता बरकरार रहे, इसलिए होर्डिंग और पोस्टर न लगाएं, होर्डिंग और पोस्टर में जो पैसा खर्च करते हैं उसे किसी भी गौशाला में दान करें। इंदौर शहर में कई गौशाला हैं जिसमें पितु पर्वत की गौशाला, मित्तल गौशाला, साई बाबा मंदिर की गौशाला सहित और भी गौशाला हैं।कार्यकर्ता बंधु और समर्थक होर्डिंग पोस्टर के पैसे का सद उपयोग कर गौशाला या वृद्ध आश्रम में पैसा दान करें, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्यकर्ता और मुझे दिल से चाहने वाले समर्थक मेरे हृदय में वास करते हैं उन्हें होर्डिंग, पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की स्वच्छता के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह अन्य नेताओं को भी कैलाश विजयवर्गीय से प्रेरणा लेकर अपने जन्मदिन पर होर्डिंग और पोस्टर से दूरी बनाना चाहिए और अपने समर्थकों और चाहने वालों से इसी तरह की अपील और निवेदन करना चाहिए कि वह होर्डिंग, पोस्टर उनके जन्मदिन पर न लगे। पर्यावरण की सुरक्षा और शहर को स्वच्छ रखने के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है जिसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। यह छोटे-छोटे कदम हमारे पर्यावरण और शहर की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। इसी से शहर स्वच्छ रहेगा क्योंकि देखा गया है जब एक समर्थक एक होर्डिंग लगाता है तो दूसरा देखा देखी दो होर्डिंग लगाता है और आपस में प्रति स्पर्धा में पूरे शहर को बैनर, पोस्टर से पाट दिया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय की यह पहल स्वागत योग्य है एवं इसका सबको स्वागत करना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों को उनके आग्रह को मानते हुए जन्मदिन पर बैनर, पोस्टर नहीं लगना चाहिए। यह पहल कर जन्मदिन का एक सच्चा तोहफा कैलाश विजयवर्गीय को कार्यकर्ताओं को देना चाहिए।

डिंडोरी जिले के जनजातीय गाँव उफरी के हर घर पहुंचा नल से जल



भोपाल(नप्र)। डिंडोरी जिले के करंजिया ब्लॉक का उफरी गांव, जहां कभी जल संकट विकराल रूप ले लेता था, अब स्वच्छपेयजल की सुविधा से आमनिर्भर हो चुका है। यह वही गांव है, जहां पानी की एक-एक बूंद के लिए ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जहां महिलाओं और बच्चों का बड़ा हिस्सा अपने दिन का अधिकांश समय पानी की व्यवस्था करने में ही गंवा देता था। अब यह सब बीते समय की बात हो गई है।

गांव के बुजुर्ग श्री गंगाराम बैंग बताते हैं, गर्मियों में पानी की इतनी दिक्रत थी कि कई बार हमें रात में भी पानी भरने जाना पड़ता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि झिरियों से गंदा पानी पीने के कारण गांव के कई लोग बीमार पड़ गए। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे गांव में भी नल से पानी मिलेगा। अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। यह हमारे लिए किसी चमकार से कम नहीं है।

भोपाल (नप्र)। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि कोई भी सरपंच, सचिव या अन्य पंचायत प्रतिनिधि उनके पास सड़क, नाली मांगने नहीं आएँ। यह काम पंचायतों को अपने वित्तीय स्रोत से करना होगा। प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की तैयारियों के बीच उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिवों तथा ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण की नीति जल्दी ही घोषित करने की तैयारी है। इन कर्मचारियों की तबादला नीति घोषित होने के बाद उसी के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे।

मंत्री पटेल ने ये बातें मऊगंज और रीवा प्रवास के दौरान कहीं हैं। उन्होंने मऊगंज में एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा कि पंचायतों के पास पर्याप्त फंड और वित्तीय स्रोत हैं। इसलिए वे सभी को कह रहे हैं कि कोई भी पंचायत प्रतिनिधि उनके पास सड़क, नाली के लिए पैसा मांगने नहीं आएगा। यह काम पंचायतों को खुद करना होगा। उन्होंने कहा कि तीस से चालीस साल पुराने जनपद पंचायत भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने का काम भी विचार करने की तैयारी कर रहा है। भवन विलीन सभी ग्राम पंचायतों को बिना मांगे पंचायत भवन तथा सामुदायिक भवन दिया जा रहा है। पंचायत भवन जो 30 से

रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव से विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के खुले हैं द्वार : उप मुख्यमंत्री शुक्ल पतंजलि संस्थान द्वारा विंध्य क्षेत्र में किए जा रहे निवेश एवं औद्योगिक परियोजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा



भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि हाल ही में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव, रीवा के माध्यम से विंध्य क्षेत्र में निवेश के नए और अपार अवसर खुले हैं। जो विंध्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। पतंजलि समूह जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की भागीदारी से इस क्षेत्र में

औद्योगिक क्रांति की मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल से अमहिया, रीवा स्थित निज निवास पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक सचिव आचार्य श्री बालकृष्ण ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर पतंजलि संस्थान द्वारा विंध्य क्षेत्र में किए जा रहे निवेश एवं संभावित औद्योगिक परियोजनाओं को

लेकर विस्तृत चर्चा हुई। क्षेत्रीय विकास, स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग तथा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों और जनभागीदारी के माध्यम से आत्मनिर्भर विंध्य के निर्माण की दिशा में सार्थक चर्चा हुई।

प्रदेश में तेज गर्मी के बीच बारिश, आंधी की संभावना भोपाल, इंदौर –ग्वालियर में गर्मी बढ़ी ; दोपहर में घर से न निकलने की सलाह

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में सूरज की तपिश तेज हो गई है। इससे गर्मी का असर भी बढ़ा है। शुक्रवार को तेज गर्मी के बीच आंधी और कहीं-कहीं बारिश हुई। मौसम विभाग ने शाम के समय शिवपुरी, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाटणा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में बिजली चमकने के साथ हल्की आंधी आने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।

शाजापुर-सीहोर जिले में जहां बारिश हुई। वहीं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के 20 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इस गर्मी के सीजन में पहली बार इतने शहर तपे हैं। कई शहरों में तो पारा 3 डिग्री या इससे ज्यादा बढ़ गया। गर्मी का असर बढ़ते ही मौसम विभाग ने लोगों को



दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। इन्हीं 4 घंटों के दौरान धूप तेज होती है और गर्म हवाएं चलती हैं। वहीं, खाना-पान और सूती

कपड़े पहनने की सलाह भी दी गई है। **नर्मदापुरम-रतलाम सबसे गर्म रहा-** मौसम विभाग के अनुसार, नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री दर्ज

भोपाल में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज कमीशन बड़ोतरी समेत कई मांगों पर देशभर से जुटेंगे 600 वितरक, आंदोलन की रणनीति पर होगा मंथन

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आई) का राष्ट्रीय अधिवेशन आज यानी 19 अप्रैल को होगा। यह अधिवेशन सुबह 10:30 बजे भोपाल के समन्वय भवन, टीटी नगर में आयोजित किया जाएगा। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से करीब 600 एलपीजी वितरक भाग लेंगे।

जिसमें तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी समेत कई राज्य शामिल हैं। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य वितरकों की लंबित मांगों पर मंथन करना और आंदोलन की रणनीति तैयार करना है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा बोले- महंगाई बढ़ी लेकिन कमीशन नहीं- राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि हम लोगों के घर पर गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। वहीं आज भी वितरकों को 40 किलोमीटर दूर तक गैस सिलेंडर



पहुंचाने पर केवल 35 रुपए मिलते हैं। जो इस महंगाई में बहुत कम है। इसलिए हम कमीशन में वृद्धि को लेकर अपनी मांग करेंगे। वहीं तेल कंपनी अपना घाटा पूरा करने के लिए हम पर जुर्माना लगाती हैं। जैसे उज्ज्वला योजना में लोग सिलेंडर महंगा होने से लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके लिए डीलर कैसे जिम्मेदार है। वो इसकी रिकवरी डीलर से करना चाहते हैं।

तेल कंपनियां जुर्माने वसूल रहीं- उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष राय ने बताया कि उज्ज्वला योजना में हम सब डटा फीडर थे और

कहा, ऐसे आयोजन आज के युवाओं को अपनी कला दिखाने का बेहतरीन मौका देते हैं। यह गर्व की बात है कि युवा कलाकारों को अपनी प्रस्तुति के लिए बेहतरीन मंच मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान हुई प्रस्तुतियों को दर्शकों



ने बेहद पसंद किया।

वहीं, सुभाष चंद्र ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों की आज बहुत जरूरत है, जो एक सांस्कृतिक ब्रांड और अंतरराष्ट्रीय पहचान की तरह काम करते हैं। वहीं, कार्यक्रम के बाद निर्द्वर कला संस्थान के संस्थापक समीर नाफड़े ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवा कलाकारों को एक ऐसा मंच देना है, जिससे वे आगे बढ़ सकें।

देशभर से आए युवा कलाकारों ने लिया भाग ; बड़ौदा की अनाहिता वानारे को पहला स्थान

भोपाल में ‘कथक अश्वमेध’ प्रतियोगिता का समापन

देशभर से आए युवा कलाकारों ने लिया भाग ; बड़ौदा की अनाहिता वानारे को पहला स्थान

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शहीद भवन सभागार में शास्त्रीय नृत्य ‘कथक’ की प्रतियोगिता ‘कथक अश्वमेध’ का दूसरा संस्करण शुक्रवार को समापन हो गया। जिसमें देशभर के युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में गुजरात के बड़ौदा की अनाहिता वानारे ने पहला स्थान हासिल किया। मनस्वी भोजने और रायपुर के शिवांश कुर्मी को दूसरा स्थान मिला, जबकि नागपुर के गणेश बोरकुटे तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और सम्मान पत्र दिए गए।

प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ घराने की प्रसिद्ध नृत्यांगना अल्पना बाजपेई, अंतरराष्ट्रीय कलाकार नीलाक्षी खंडकर सक्सेना, कथक गुरु सुभाष चंद्र और प्रसिद्ध तबला वादक पंडित मनु राज पचौरी जैसे दिग्गज उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन निर्द्वर कला संस्थान, नागपुर ने किया था। **सांस्कृतिक कार्यक्रम को दर्शकों ने किया पसंद-** इस दौरान अल्पना बाजपेई ने

विश्व स्तर पर स्थापित सत्य है कि भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकातांत्रिक देश है। एक ऐसा देश जहाँ लगभग डेढ़ अरब लोग निवास करते हैं। जनसंख्या के लिहाज से यह इतना बड़ा अंकड़ा है कि भारत का एक-एक ग्राहक अपने भीतर एक से अधिक राष्ट्र समाहित कर लेता की हद तक फैला हुआ है। फिर भी हमारे देश के नागरिक बेहद आधुनिक चुनाव पद्धति के माध्यम से ग्रामीण, शहरी जनपदीय, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भली-भांति हमारे देश की सरकारों का गठन लोकतांत्रिक प्रणाली से कर रहे हैं। आज जब स्वयं को विकासशील और विकासतक पहुँचाने वाले एक राष्ट्र मत पत्र आधारित चुनाव प्रणाली में ही उतरे हुए हैं, लेकिन तब हमारा भारत देश अत्यन्तक चुनाव प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक का सफर तय कर चुका है। एक जमाना ऐसा था जब हमारे यहां भी मत पत्र प्रणाली पर आधारित चुनाव प्रक्रिया व्यवहार में लाई जाती थी। लेकिन इस देश ने और देश के अनुभवाचारों ने मतपत्र प्रणाली पर आधारित चुनाव प्रक्रिया को चुनते हुए अनेक प्रतिकूल, बेहद खतरनाक परिणाम भी देखे। कई दशकों तक ये न केवल प्रकारों सत्ता पर काबिज बने रहने अथवा सत्ता पर काबिज होने के लिए मतदान प्रणाली की साविकता का हथकण किया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर अनेक अवसरवादी, सत्ता लोलुप और नैतिकता से लगभग नाता तोड़ चुके घाघ राजनेता बूढ़े कैप्टनशिप करते रहे। नकली मत पेटियाँ से असली मत पेटियाँ बदली जाती हुई। चुनावी ठीम को एक प्रकार से अहताक करते हुए मारपसर्स उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर यंत्रबत ठपे लगाए जाते रहे। इस पाप पूर्ण कृत्य का विरोध करने पर जागरूक मद्रदाताओं, चुनाव करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, पत्रकारों को मौत के घाट उतारा जाता रहा। फलतः एक समय ऐसा भी आया जब उत्तार की पंचायत से लेकर देश की लोकसभा तक, विभिन्न सदन में, बाहुल्य के बल पर जीत कर आए, अपराधितक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ गई जब देश के निधिय भागों में भ्रिन्न-भिन्न चुनाव रक्त रजित होने लगे, तब देश के प्रबुद्ध वर्ग को चिंता हुई। यह विमर्श करने के बाद, अपराधी किस्म के नेता भूत कैप्टनशिप का कर्तृपाप यह संवुति करके मशीन आधारित चुनाव प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आधारित चुनाव प्रणाली को

छल छः देवका सं देश में नासूर बनकर उभर
नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुँच गया है।
देश के गुजराती अभिमत शासन ने संसद में घोषणा की है कि वि
31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर
दिया जाएगा। गुह नहीं द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी
घोषणा है। वह 60 वर्षों से देश नक्सलवाद की समस्या से
बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई संसर्गों आ
और चली गईं मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों-दिन
बढ़ता ही रहा था। देश के कई प्रशांतों ने तो बहुत बड़े हिस्से
में नक्सलवादी अपनी समाप्तांतर सरकार तक चलाते थे।
नक्सलवाद प्रभावित जिलों में उनकी कुदृष्टम चलती थी।
वहाँ केंद्र व राज्य सरकार का कोई असर नहीं दिखता था।
नक्सलियों का परमान ही अभिमत आदेश होता था जिस
लोग मानने को मजबूर थे। मगर अब परिस्थितियाँ पूरी तरह
बदल चुकी हैं। केंद्र सरकार की नक्सलवाद से मुक्त के
अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम साँसें
पिन रहा है। कई बड़े-बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से
मुठभेड़ में डेर हो चुके हैं या फिर उनसे सरेख कर अपनी
जान बचा ली है। केंद्रीय गुह नहीं अभिमत शासन ने पिछले
दिनों कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा
में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उदाव से
अति प्राभावित जिलों की सख्या 12 से घटकर 6 कर दिया
है। शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी
सरकार के दृष्टिकोण पर परशान डालते हुए अपनी सभी क्षेत्रों

सामयिक

अवधेश कुमार

लेखक पत्रकार हैं।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर मध्यप्रदेश का गुना और उसके पहले नासपुर, मलाहा आदि की घटनाओं से निस्संदेह तक को डना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि डर कर नुसुचाप बैठ जायें बल्कि इन घटनाओं की लगातार दिख रहे यथार्थों के पहचान कर उसके अनुसूच्य व्यवहार करने का समर्थ है। मुर्शिदाबाद से भागीरथी नदी में नाव पर बड़े कठोर पलायन करते और फिर मालदा जिले में उतरते लोगों का तस्वीरें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अंदर से हिला देती। इस पश्चात्किस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों को के बारे में क्या कहेंगे? मालदा के पारलपुत्र हाई स्कूल में शरण लिए लगभग 500 लोगों की तस्वीरें एवं वक्त्रचित्र के सामने लगे हैं। इनमें तीन दिन के नवजात बच्चे से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। स्वजातीय स्थानीय लोगों ने कम से कम उन्हें लगे लगे लाया और खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। भाषा प्रदेश अथवा अख्यक्ष सुकाना मजुमदार की यात्रा के बाद पार्टी और दूसरे हिंदू विधेय संसदन भी सक्रिय हुए। लेकिन क्या किसी को झारखंड में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हिंदू असम और श्राद्धहृद में पहुंच गए। निषेधन के अंतर्गत लौट आने वाली नौ दैतेश को पता भी नहीं था। जब असम के मुख्यमंत्री हिमांतो बिस्वासर्मा ने अपनी पोस्ट लिखा

वीथिका

भारत की चुनाव प्रणाली ने वैश्विक स्तर पर पाई प्रामाणिकता

वर्ष 1982 में केरल राज्य के उत्तरी पारावुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम आधारित चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। यह चुनाव उम्मीद से कहीं आगे जाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान के परिणाम भी पारंपरिक मत पत्रों पर आधारित चुनाव प्रणाली की अपेक्षा बहुत जल्दी प्राप्त हो गए। अपवाद स्वरूप प्राप्त बेहद सीमित आपत्तियों के अलावा कोई उल्लेखनीय खामी सामने नहीं आई, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आधारित चुनाव प्रणाली को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। बाद में जब विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो इसकी पारदर्शिता और सात्विकता पर अनेक उंगलियां उठीं। फलस्वरूप देश के चुनाव आयोग ने राज्यसभा, लोकसभा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के अलावा कलेक्टरेटों में, और जहां तक संभव हो सकता था वहां तक इन मशीनों का प्रदर्शन किया।

माना लिया। इस प्रकार वर्ष १९८२ में केरल राज्य के उत्तरी पारवुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम आधारित चुनाव प्रणाली को इस्तेमाल किया गया। यह चुनाव उम्मीद से कहीं आगे जाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान के परिणाम भी परंपरिक मत गणना पर आधारित चुनाव प्रणाली की अपेक्षा बहुत जल्दी प्राप्त हो गए। अपवाद स्वरूप प्रांत बेहेट सीमित आपत्तियों के अलावा कोई इलेक्शनीय प्रश्नों सामने नहीं आईं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आधारित चुनाव प्रणाली को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। बाद में जब विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो इसकी पारदर्शिता और सात्विकात्म्य पर अनेक उंगलियाँ उठीं। तब स्वल्प देश के चुनाव आयोजन ने राज्यसभा, लोकसभा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के अलावा इलेक्ट्रेटरों में, और जहां तक संभव हो सकता था वहां तक इन मशीनों का प्रदर्शन किया। सभी स्तर के आम और खास लोगों को इसकी प्रक्रिया बताई व दिखाई गई। साथ में शिक्षायंत्र सुझाव एवं आपत्तियां संग्रहीत हुईं। हर एक शिकायत को सुझाव पर भारी की गई बिचार विमर्श करके समाप्त किया। जो सुझाव उचित लगे उन्हें व्यवहार में लाया गया। निष्कर्ष निकाला कि ये शिकायतें अथवा आपत्तियां में ताकिंकता दिखाई दी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से निराकृत किया गया। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सात्विकात्म्य, उनकी पारदर्शिता को लेकर व्यापक स्तर पर संतुष्टि काजिज हो गई, तब कहीं जाकर इस

[illegible]

उनके मुताबिक देश के नागरिक बार-बार के चुनावों से तंग आ चुके हैं। बात सही भी है, कोई साल और महीना ऐसा नहीं बीताता जब देश के किसी प्रांत, जिले, नगर, जनपद अथवा गांव में चुनाव संपन्न ना होता हो। परिणामस्वरूप आम आदमी दो बार-बार के चुनावों से तंग तो आया ही, चुनावी आचार संहिता के बने रहने से विकास कार्य भी प्रभावित बने रहते हैं। आम आदमी के साथ-साथ विकास की गति को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव की पुजुरो वकालत कर रहे हैं। यदि यह चुनाव प्रणाली देश में लागू होती है तो फिर आम आदमी को विभिन्न पदों के निर्वाचन हेतु बार-बार मतदान केंद्रों पर नहीं भटकना पड़ेगा। इससे मतदाताओं के अंतर्गम में गहरे तक पैठ चुकी ऊब से छुटकारा मिलेगा तथा मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सकेगा। इसी के साथ विकास कार्य भी निरंतरता के साथ संपादित किये जा सकेंगे।

इसका मतलब यह हुआ कि भारत को वर्तमान चुनाव प्रणाली बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन करने कर रही है। उसको पारदर्शिता और सात्विका वैश्विक स्तर पर प्रामाणिका प्राप्त कर चुकी है। ऐसे में यदि एक और नया चुनाव प्रणाली की बात की जाए तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है तो फिर एक और नया प्रयोग क्यों? इसका जवाब कुछ यूँ हो सकता है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, यह सोचकर हाथथ पैर हाथ रखकर बैठते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए - अभी भी चुनाव कराने के लिए लाखों पोलिंग बूथ करोड़ों चुनाव

र पहुंचा नक्सल

है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया था है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूटलाइन किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। पिछले 20 वर्षों में 2,344 गुवाहाटी में नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाए हैं पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जिन देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियों के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था।

सरकार एक तरफ जहाँ नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं

आधिकारी – कर्मचारी, सुरक्षा बलों की व्यापक स्तर पर मौतदान, भारी पैमाने पर आर्थिक खर्च तथा आम आदमी की तैनाती, भर्ती दोनों तक आजादी, वह सम्स्याएँ हैं जिनका हल हमें आज ही ढूँढना होगा। क्योंकि जैसे-जैसे मतदान प्रतिष्ठित बढ़ेगा, व्यवस्थाएँ, नियुक्तियाँ और खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ते चले जाने हैं। इन सभी के निराकरण स्वरूप दिमाग में एक संभावित चुनाव प्रणाली का ध्यान आता है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग सिस्टम। यदि इस प्रणाली पर व्यापक बातें, बहस, विमर्श आदि हों तो परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सारगर्भित नतीजों से भारतीय लोकतंत्र के लिए नई संभावनाओं की तरफ़ा हा सकता है। लेकिन इसके लिए, पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग सिस्टम काम कैसे करेगा।

इसका सबसे पहले चरण होगा मतदाता का पंजीयन। यह आधार कार्ड या किसी डिजिटल आईडी का उपयोग करके चुनाव आयोग द्वारा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।

दूसरे कम पर आती है मतदान प्रक्रिया। इसे संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता को एक डिजिटल मतदान अथवा कोड प्रेषित करेगा, जिसके माध्यम से मतदान जहाँ है वहाँ से मान्यता प्राप्त गैजेट को माध्यम बनाकर अपने मनपसंद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकेगा। बदले में उसे डिजिटल स्वरूप में ही तत्काल मतदान को रसीद चुनाव आयोग द्वारा भेजी जा सकेगी। मतदाता द्वारा चुनाव आयोग को भेजा गया उपरोक्त मतदान ब्लॉक चैन सिस्टम में दर्ज होगा जिसे बदला नहीं जा सकेगा।

तीसरे क्रम पर मतगणना की बारी आती है। हांगा यह कह कि जैसे ही मतदान संपन्न होगा और मतगणना के लिए सिस्टम का सर्वे अनं किया जाएगा, वैसे ही डिजिटल स्वरूप में मतगणना के परिणाम मतदान में इस्तेमाल किए गए गैजेट पर दिखाई देने लगेंगे। मतगणना में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है, यह रद्धान भी ठीक उसी प्रकार प्रदर्शित हो सकेगा जिस प्रकार स्टॉक मार्केट में शेयरों के भाव उतार-चढ़ाव के रूप में देखा जाना प्रचलन में बना हुआ है। अंत में यह परिणाम भी देखा जा सकेगा कि चुनाव में कौन हारा और जीत किसके हिस्से में आई। ब्लॉक चैनल वोटिंग सिस्टम के एसस्प्लोर का उपयोग करके हार जीत का अंतर क्या रहा, यह भी बगैर लंबी प्रतीक्षा के तत्काल देखा जा सकेगा। खास बात यह कि इस चुनाव प्रणाली में भी डिजिटल सिस्टम से दर्ज हुए आंकड़ों में किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि सारा डेटा इंक्रिप्टेड और सुरक्षित ही रहने देखा है।

समाप्त होने के कगार पर पहुंचा नक्सलवाद

में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश को प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सरकारी, सुस्थित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गुप्त मात्राला के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वाघपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकुमा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरोली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता के जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है 9 से घटकर 6 रह गई है। ये जिले आंध्र प्रदेश में अहली सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोयलगुडम हैं।

अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपगढ़ और तेलंगाना का मुनुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वित्तीय

सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

नक्सलवाद क खिलाफ जारी टॉरेंट्स की नीति क चलते बंधे 2025 में अब तक केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गए आंकड़ों के अनुसार खूनीसमय में मुम्बई में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संघा में मारे गए जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत साते जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूलाइज किया गया था 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूलाइज किया जा सका है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टनाइट पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 162 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैम्प और 68 ग्राट लीडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़े 1,64,633 हिंसक घटनाएँ हुई थीं लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई

है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। लेकिन पिछले 10 साल में कक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया था है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूटलाइन किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। पिछले 20 वर्षों में 2,344 गुवाहाटी में नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाए हैं पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जिन देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियों के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था।

सरकार एक तरफ जहाँ नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं

नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अपनी विचारधारा फैलाते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं।

देश में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों का असर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद-मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश में वामपंथी उठावाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आना इस आंदोलन की समाप्ति के संकेत है।

नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने भी नक्सलवादी विरोधी अभियान में अपनी शहादत दी है। एक समय था जब देश के 10 प्रांतों में नक्सलवादियों की तूती बोलती थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला कर दिया था। जगदलपुर में तो नक्सलवादियों ने काग्रेस के कई बड़े नेताओं की हत्या कर सनसनी फैला दी थी।

मगर अब कैसे सरकार को नीतियों के कार्यान्वयन क्षेत्रों जहाँ इन पर दबाव बढ़ा है वहीं उनसे प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार ने विकास को योजनाएँ प्रारंभ कर उनका जन समर्थन समाप्त कर दिया है। कई बड़े नक्सली कमांडों का एनाकांडेर होने के बाद डर कर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जिससे आने वाले समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व्याप्त होगी। जो सरकार व आमजन को एक बड़ी जीत होगी।

मुर्शिदाबाद हमारी चिंता का कारण होना चाहिए

तब इसकी जानकारी हुई। वर्तमान घटना में पलायन कर गए लोग मुर्शिदाबाद के धुलियान के हैं। वे बता रहे हैं कि घरों में आग लगा दी, मारपीट की गई, अब न घर रहा न लोगों को राशन बाधा हम कर रहे तो क्या करें, जो कुछ था वह सब लूट कर ले गए। मणिपुर पर तूफान खड़ा करने वाले और यात्रा करने वाले राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के नेताओं की चुप्पी ज्यादा डरावनी है। मणिपुर देश के लिए सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए किंतु क्या मुर्शिदाबाद नहीं?

यही वह प्रश्न है अलग-अलग ऐसी घटनाओं और संदर्भों में जिनका उत्तर भारत स्पष्ट रूप से कभी नहीं दे सका। धुलिगाना में एक परीषद पितृ पुत्र की हत्या कर दी गई जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे। मूर्तिकार से किसका वेर का हो सकता है? लोग कर रहे हैं कि उनकी पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक तो मतभ्रम बनाई सरकार को धुलिगाना जाँच करके देना चाहिए था। नहीं बाने का मतलब? हमें तालाबों में मछलियों सहित अन्य जीव मरे पाए गए। यानी हमलवार घोषणा कर रहे थे कि सारे पानी में जहर मिला देगे तो संभवतः उन्हीं तालाब में ऐसा किया। टीवी कैमरों के माध्यम से देश ने वहां की हिंसा देखी। इन पक्षियों के लिखे जाने तक भी अलग-अलग क्षेत्र में हिंसा हो रही थी। यमशेरगंज सहित कई स्थानों में बीएसएफ की टीमी पर गोलीबारी की गई। बीएसएफ कई घरों में जमा किए पत्थर हटा रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के कारण केंद्रीय सुरक्षा बलों की 17 कंपनियाँ नैतक की गई अन्यथा पश्चिम बंगाल पुलिस के रहते वहां हो रहा था और यथा होता इसकी कल्पना से रंगेंट खड़े हो जाते हैं।

भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भले आप आलोचना करिए और उनसे विरोध भी हैं। इन विरोध पर परिस्थिति में मैं हिंदू समाज के साथ इनसे अलगाव कोई खड़ा नहीं दिखता। आपने पार्टियों की स्थानीय ईकाइयां सच देखी हैं, भूमिका समझता भी चाहती हैं लेकिन प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में नहीं करती। सबसे मुझे स्थिति कांपस के पिछले लोकसभा में पार्टी के नेता और रंजन चौधरी भी हैं। उसकी बात पार्टी में ही गुप्त रूप से बता कर कोई नहीं क्योंकि यहाँ पर है। उनका का मुस्लिम वोट बैंक भाविगत होता है। स्थानीय भाजपा के कई नेताओं ने प्रदेश में शराबख बल विरोध पर शक्तियां अधिभियोग या अपसर्ग लागू करने की मांग की है। आपको यह भले नावाग गुरो कि पत्रों पंडित को स्थिति को देखिए और निष्कर्ष निकालिए कि वहां क्या स्थिति जाना चाहिए? किसी का वक्फ संशोधन कानून से विरोध है तो उसका तरीका हिंदुओं पर हमला कैसे सकता है? वैसे तो वक्फ कानून में ऐसा कुछ नहीं है इससे मुसलमान या इस्लाम के वरुद्ध साबित किया जा रहा है। जस तरह की जहर फैलाने वाले वास्तव में स्वयं मुस्लिम समाज के ही दुश्मन हैं। बावजूद आप आपको विरोध करना है तो इसके लिए हिंदुओं के घरों पर हमले करने, धर्म स्थलों को क्षतिग्रस्त करने, हत्याएं करने, डकान घर जलाने आदि की क्या आवश्यकता है?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था। क्या हिंसा के लिए उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए? हमलावरों की तैयारी कितीनी थी यह है इसका अंशमान इसी से लगाएँ कि पलायन कर गए लोग बता रहे हैं कि ये भूमि सिलेंडरों को खोलकर पित्तारसाईं से आग लगा रहे थे और मेट्रोले डाल रहे थे। आगजनी, पित्तारबाजी और गोली चलाने के

लेए पहले की तैयारी चाहिए। गुना में हनुमान जयंती की शोभायात्रा पर जितनी भारी सँख्या में पथर चल और आंगजनाइ उन्की तैयारी एकाएक सभव नही। इसी तरह हजारीबाग में एह दुहुआ। पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हिंदुओं से जुड़ उठकलकों, शोभा यात्राओं, फिर विमसजनों आदि पर इसी तरह पथरों से हमले होते हैं, फिर अगिनकाइ होता है। इससे भी डरावना सभ्यता से हमले होते हैं कि कोंते बड़ू मुस्लिम नेता या संगठन इससे के निर-ड मुमुख होकर सामने नही आते। दूसरे पक्ष को ही दोषी ठहरे के अभियान चलता है और कहा जाता है कि हमले उन्ते उकसान पर हु। किसी के उकसान पर हजारा- लाखों की सँख्या में पथर, पेट्रेल बम पैदा हो सकते। मुर्शिदाबाद पर बंगाल की ममता सरकार में मंत्री सीतुकुल्लु चौधरी कर रहे हैं कि हिंसा में भारी और भाजपा के लोग शामिल थे, वे बीएसएफ की गोलियों से मारे गए। जंगीपुर के स्थानीय तुमूल सॉसंद खलीलुर रहमान का कथन भी यही है। तुमूल प्रवक्ता कुणाल घोष का वक्तव्य है कि सभ्यता राजनीतिक दल ने बाहर से अपराधियों को लाकर बीएसएफ के सहयोग से मुर्शिदाबाद में तांडव मचाया है।

ममता सरकार और उनकी पार्टी का स्टैंड यही है तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं है। पिछले वर्ष लगभग इसी समय जब वर्षमान जिले में एक बम विस्फोट की जांच करने गईं मुआयिदा की टीम पर जबरदस्ती हमले हुए। विस्फोट बम बनाने के दौरान हुई और मरने वाले तीनों तुणमूल के थे। जाहिर है इसमें किसके गले तक हाथ पहुँचा। चाहे शाहजहाँ के संस्थान पर ऊर्दे हैं किने गईं ममता हो या आम जगह वहाँ हमेशा बड़ी संख्या में कार्रवाई विरोध का सामना करना पड़ता है खदेड़ा जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर पूरी सरकार, पाँच

हमला बोल शैली में साथ खड़ी होती है। जब सरकार और पुलिस प्रशासन का भय नहीं हो तो कट्टरवादी तत्व ऐसे ही उन्माद फैलाता है।

तो सच को सच की तरह देखिए फिर रास्ता निकालिए।
क्या हो सकता है। बंगाल संपूर्ण देश के लिए ऐसा डरावना प्रश्न
नभाना हुआ है जिसका अभी तक उत्तर नहीं मिला है। धीरे-धीरे
दूसरे राज्यों में भी हिंदू उत्सवों प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्राओं
आदि पर हमले की प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं। उनके संधर्भ में हिंदू संप्रदाय,
संस्कृत तथा पाठियों को नभाने पर सभसे अपुनी स्थिति रणनीति और
व्यवहार तय करनी होगी। मुस्लिम समुदाय के अंदर भी डरावदी
तबके को उनके विरुद्ध खुलकर सामने आना चाहिए। यह देश
बचाने का प्रश्न है। लेकिन जो समाज अपनी आत्मरक्षा और
प्रतिरोध की शक्ति खो देता है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता।
इस समय हिंदू समाज विवधान के तहत हिंसा या गलत के
प्रतिरोध के अंधकार तक का इस्तेमाल करने का साहस नहीं
देखे रहा। कम से कम ऐसी घटनाओं के विरोध में अहिंसक
प्रतिक्रिया से भरना प्रदर्शन जैसे प्रतिरोध तो होना चाहिए था।
बावजूद बंगाल जैसे स्थिति किसी की नहीं। केरल की
कुछाति भी बंगाल के सामने कमजोर काफ छेदी हो गई है।
न्यायालय की स्थिति यह है कि 2021 में हिंदुओं के पतयान
का मामला उच्चतम न्यायालय में आया और सुनवाई के दौरान
कुछ बंगाली न्यायमूर्ति ने पहले अपने को अलग किया। फिर
सुनवाई आरंभ हुई और एक और बंगाली जज साइब ने स्वयं
को अलग कर लिया। इस कारण वह बाधित रही। वैसे भी
न्यायालयों ऐसी बढ़ती या स्थानों हो चुकी प्रवृत्तियों का समाधान
नहीं कर सकती।

भोपाल की सरकारी बिल्डिंग में दो मजार

भोपाल (नप्र)। भोपाल की सरकारी बिल्डिंग में दो मजारें बना ली गई हैं। बकायदा यहां इबादत भी की जा रही है। हिंदूवादी संगठन ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए एसडीएम से शिकायत की है।



मामला भोपाल के शासकीय आवासीय क्षेत्र 1250 का है। संस्कृति बचाओ मंच ने इस पर आपत्ति जताई है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा- 1250 इलाके में आवास क्रमांक-28, 38 और 85, 96 के आसपास दो मजारों का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। वीवीआईपी इलाके के सरकारी भवन में दो मजारें कैसे बन गई? भोपाल में लैंड जिहाद चल रहा है।

करीब तीन साल पहले बनाई गई मजारें- तिवारी ने गुरुवार को टीटी नगर एसडीएम अर्चना रावत को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कहा कि इन मजारों को हटवाने की कार्रवाई करें ताकि बेशकीमती भूमि अतिक्रमणमुक्त हो सके। यदि अतिक्रमण नहीं हटया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

इस पर एसडीएम रावत ने शुक्रवार सुबह पटवारी को मौके पर भेजा। जांच में सामने आया है कि मजारें करीब तीन साल पुरानी हैं। इन्हें किसने बनाया या बनवाया, ये साफ नहीं हो पाया है। इन मजारों के आसपास मुस्लिम फैमिली रहती हैं। मजार के सामने ही बाघमेश्वरी देवी मंदिर है।

कोलार एसडीएम का इलाका, जानकारी दे रहे- पटवारी की जांच रिपोर्ट की जानकारी देते हुए एसडीएम अर्चना रावत ने कहा- जिस इलाके में मजारें बनाई गई हैं, वह कोलार एसडीएम के क्षेत्र में आता है। मामला वहां पहुंचाया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं ताकि वो सही जगह शिकायत कर सकें। उचित कार्रवाई होगी।

मध्यप्रदेश में पहली बार युवा कांग्रेस की मेम्बरशिप लॉन्च

भोपाल (नप्र)। भोपाल की कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शुक्रवार को युवा कांग्रेस संगठन (आईएनएस) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आईएनएस ने मध्यप्रदेश में पहली बार ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर पार्टी के चुनाव और मेम्बरशिप का ऐलान किया है।



आईएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि अब ऐसा दौर शुरू हो रहा है, जब पार्टी के युवा नेता सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे, न कि उन्हें नामांकित किया जाएगा। यह बदलाव भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक है और यह सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। इससे पहले भी आईएनएस आंतरिक चुनाव कर चुका है।

निष्पक्षता के लिए राज्य स्तर पर टीम बनाई गई- राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि यह कदम राहुल गांधी के विजन का हिस्सा है, जब वे साल 2008 में आईबायसी और एनएसयूआई के प्रभारी थे। इस प्रक्रिया से हर क्षेत्र के युवकों को राजनीति में उतरने का मौका मिलेगा। वहीं, चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जोनल और राज्य स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की टीम तैनात की गई है।

इसके लिए एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। जिसमें 27 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक नामांकन चलेगा। 7 से लेकर 9 मई तक स्कूटी का काम किया जाएगा। उसी के आधार फाइनल कैडिडेट की लिस्ट 11 मई तक प्रकाशित होगी।

बदनावर में कंटेनर और कार की टक्कर, एक की मौत

बदनावर (नप्र)। बदनावर के पेटलावद रोड स्थित नागेश्वर मंदिर के पास शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ। करीब 8 बजे तेज रफ्तार कंटेनर और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार राजगढ़ निवासी पूजा जैन (32) की



मौके पर ही मौत हो गई। उनके पति नयन जैन (34) गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार उज्जैन स्थित ससुपाल से राजगढ़ लौट रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की ड्रइवर साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कंटेनर में लगा पाइप गाड़ी चला रहे नयन के हाथ को फाड़ता हुआ पीछेकी सीट पर बैठी पूजा के गले में जा घुसा। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीर अनिल बेरागी और अन्य लोगों ने आरी से पाइप को काटकर नयन के हाथ को निकाला। कार में सवार जुड़वा बेटियाँ और नयन के भाई चयन जैन को मामूली चोटें आईं। 108 एम्बुलेंस से घायलों को बदनावर अस्पताल लाया गया।

राजधानी आसपास

एअर-इंडिया की एयर होस्टेस की कार नहर में गिरी, मौत

भोपाल में दोस्तों के साथ घूमने निकली थी; सामने गाय आने से गाड़ी बेकाबू हुई

भोपाल (नप्र)। भोपाल में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार कार कोलार नहर में गिर गई। हादसे में एअर इंडिया की एयर होस्टेस हर्षिता शर्मा (21) की मौत हो गई। वह अपने दो दोस्तों के साथ घूमने निकली थी। कार चला रहे दोस्त जय ने बताया कि सामने अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी।

हर्षिता को गंभीर हालत में एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। हादसे में दो दोस्तों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने गाड़ी चला रहे जय

के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।

भाई से कहा था- बर्थ डे पर भोपाल आऊंगी- एयर होस्टेस हर्षिता के पिता प्रदीप शर्मा ने बताया कि वह अक्सर शहर से बाहर रहती थी। बुधवार रात उसने भाई को वॉटरसेप पर बताया था कि शुक्रवार को भोपाल आ रही है। हमें नहीं पता था कि वह गुरुवार को ही भोपाल



पहुंच गई थी। वह मिनाल रेसीडेंसी के पास होटल में रुकी थी।

दोस्तों ने फोन पर बताया- वो अस्पताल में है- परिजन को हादसे की जानकारी तब मिली, जब हर्षिता की दोस्त शिवानी का कॉल आया कि वह अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि हर्षिता बेन डेड हो चुकी है। शुक्रवार सुबह उसे मृत घोषित कर दिया गया।

विवेकानंद एकेडमी परिसर में विश्व विरासत दिवस पर सोहागपुर के इतिहास का वर्णन, छात्रों से प्रश्नोत्तरी



हीरालाल गोलांनी सोहागपुर। विवेकानंद एकेडमी परिसर में विश्व विरासत दिवस पर सोहागपुर के इतिहास पर व्याख्यान माला का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र कार्यालय एवं मंदिर सर्वेक्षण परियोजना भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह के आतिथ्य एवं नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉ भुवन विक्रम विस्तृत व्याख्यान देते हुए बताया कि सोहागपुर का इतिहास 1500 वर्ष से पूर्व का है, कई इतिहासकार 40 हजार वर्ष का इतिहास बताते हैं। इसी क्रम में पुरातत्ववेत्ताओं ने प्रोजेक्ट के माध्यम से सोहागपुर के इतिहास का भी वर्णन बताया। इसकी के साथ विवेकानंद एकेडमी परिसर में इतिहास पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहीं करीबन विभिन्न शालाओं के करीबन 30 छात्र छात्राओं से डाक्टर भुवन विक्रम ने

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करके वाद संवाद किया गया। करीबन तीन घंटे तक व्याख्यान माला में सारांशित उल्लेख से गणमान्य नागरिक को सोहागपुर के इतिहास की जानकारी से अवगत कराया गया।

क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह ने विवेकानंद स्कूल क संचालक अनिल गहैया, एवं वकील प्रांजल तिवारी को बधाई देकर कहा यह एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया सोहागपुर का इतिहास आज हमने देखा एवं सुना सोहागपुर का इतिहास बच्चों को जानना चाहिए कि हम एक बड़ा पौराणिक शहर के निवासी है।

छात्र मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल में अपने भारत की विरासत को देखें इतिहास देखें यह महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद विद्यालय प्रिंसिपल अनीता गहैया सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इसी अवसर पर सुभाष पटेल के द्वारा प्रदत्त यथार्थ गीता के प्रतियां प्रदान की गई। इन प्रतियों को अतिथियों एवं सहभागिता करने वालों को प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में मंदिर सर्वेक्षण में डाक्टर भुवन विक्रम भी शामिल थे।

मनावर में बारातियों से भरी बस पलटी, महिला की मौत, 12 घायल

मनावर (नप्र)। मनावर में मान नदी किनारे ब्रेक फेल होने से बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में नागदा जंक्शन की बबीता (35) की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं। घटना शुक्रवार सुबह 10.30 बजे की है। दारअसल, नागदा जंक्शन से बारात बड़दा पुर्नवास जा रही थी। बस में सवार बाराती मान नदी में नहाने के लिए रुके थे। नहाने के बाद जब सभी बस में बैठे, तब अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। जिससे वह नदी के समीप गड्ढे में जा गिरी।

कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रही थी महिला- मृतक बबीता के दो बच्चे हैं। दूल्हे राजपाल सिंह के पिता भगवान सिंह ने बताया कि बबीता कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बस उनके



ऊपर पलट गई। बकानेर बीएमओ डॉ. वीरेंद्र कुमार धारवे ने मौके पर बबीता की मृत्यु की पुष्टि की। बकानेर चौकी प्रभारी अश्विन चौहान ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है और राहत कार्य जारी है। पुलिस घायलों की पहचान कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।

कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर समर्पित होकर कार्य करना होगा तभी हमारा मिशन मत्र सफल और सशक्त होगा: हरीश चौधरी

देश का खजाना खाली कर दिया : जीतू पटवारी

भोपाल । मप्र कांग्रेस के प्रभारी श्री हरीश चौधरी (विधायक) और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने आज छतरपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक बैठक ली।

मप्र प्रभारी श्री हरीश चौधरी ने कहा कि कि देश तानाशाही ने नहीं, विचारों और विजन से चलता है, देश में मोदी का और प्रदेश में मोहन यादव का विकास और जनता के अधिकारों, सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए कोई विजन नहीं है, वे तो जनता को भ्रमित कर केवल टेलीविजन पर अपनी छवि चमकाने में माहिर हैं। कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस संगठन के लोग जब जनता की आवाज बनकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट और सक्रिय रहेंगे तो हर तानाशाही ध्वस्त हो जायेगा। श्री चौधरी ने पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ताओं से संवाद कर समग्रता एवं सामंजस्य की सोच के साथ संगठन का विस्तार हर गांव, गली, मोहल्ले तक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह समय संगठन के नवसृजन का है और एक-एक कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य करना होगा तभी



हमारा मिशन मध्यप्रदेश सफल और सशक्त होगा।

श्री पटवारी ने आज छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये संगठन की मजबूती और भाजपा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार आदि मुद्दों पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की जनता से जो वादे किये थे कि बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, किसानों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन मोदी राज में न बेरोजगारी दूर

जिम में कारोबारी को आया हार्ट अटैक, मौत जबलपुर में डंबल रखने के बाद अचानक नीचे गिर पड़े

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर में जिम में एक्सरसाइज कर रहे एक कारोबारी को हार्ट अटैक आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार सुबह करीब 7.30 बजे की है। इसका वीडियो भी सामने आया है।

मृतक का नाम यतीश सिंघई (उम्र 51 वर्ष) है, जो पेशे से कारोबारी थे। यतीश रोजाना करीब एक से डेढ़ घंटे तक जिम में एक्सरसाइज करते थे। शुक्रवार सुबह वे अचानक नीचे गिर पड़े। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि यतीश सिंघई हाथ में डंबल लिए जा रहे हैं। तभी कुछ प्रेशानी महसूस होने पर वे डंबल को नीचे रख देते हैं। इस दौरान उनकी चाल धीमी हो जाती है। वे थोड़ी आगे बढ़ते हैं और फिर अचानक नीचे गिर पड़ते हैं।

ये देखकर उनके ट्रेनर और बाकी लोग उनके पास पहुंचते हैं। उनकी पीठ और सीने पर मालिश करते हैं। कोई हरकत नहीं देख उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में जरूरी जांच के



बाद डॉक्टर ने यतीश को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, यतीश की मौत दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने से हुई।

सीने में दर्द था, फिर भी एक्सरसाइज की- यतीश सिंघई शहर के गोरखपुर थाना क्षेत्र स्थित गोल्ड जिम में पिछले कई महीनों से नियमित

रूप से एक्सरसाइज करने आ रहे थे। यतीश के ट्रेनर ने बताया कि सुबह जब वह जिम आए थे, उस दौरान उनको हल्का-हल्का सीने में दर्द हो रहा था, तब उन्हें आराम करने की सलाह दी गई थी। यह भी कहा था कि आज एक्सरसाइज न करें और ज्यादा वजन भी न उठाएं। इसके बाद भी वह हैवी वेट से प्रेक्टिस कर रहे थे।

डॉक्टर बोले- हार्ट अटैक की कोई एक वजह नहीं होती- कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिलीप तिवारी ने बताया कि हार्ट अटैक आने की कोई एक वजह नहीं होती। देर रात तक जागना और जल्दी उठना, डाइट फॉलो न करना, नशा करना जैसे कई कारण हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जनिको कोरोना हुआ था, उन्हें भी सावधानी की जरूरत है। वहीं, गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल ने कहा- अभी तक थाने में कोई जानकारी नहीं आई है। परिवार वाले भी थाने नहीं पहुंचे हैं। यह जरूर है कि आज सुबह जिम में एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसका कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में जल संकट पर बीजेपी

सरकार की नाकामी : मुकेश नायक

भोपाल । मध्य प्रदेश में जल संकट की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और यह संकट अब राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा चुका है। लाखों लोग पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसने उनकी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभागाध्यक्ष मुकेश नायक ने इस गंभीर स्थिति के लिए बीजेपी सरकार की नीतियों और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और जनविरोधी फैसलों ने मध्य प्रदेश की जनता को इस संकट की आग में झोंक दिया है। यह एक ऐसा संकट है जो केवल कांसजी योजनाओं और बड़े-बड़े वादों से हल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए ठोस कदमों और जवाबदेही की जरूरत है, जो बीजेपी सरकार में नहीं नजर नहीं आती। राज्य के अलग-अलग हिस्सों से जल संकट की ऐसी कहानियाँ सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं और सरकार की विफलता को साफ तौर पर उजागर करती हैं। इछवर विधानसभा क्षेत्र, जो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का अपना क्षेत्र है, वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यह सोचने वाली बात है कि एक मंत्री के क्षेत्र में भी लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के लंबे कार्यकाल के बावजूद, इस क्षेत्र के गांवों में आज भी मूलभूत जल सुविधाओं का अभाव है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सरकार ने न केवल आम जनता की अनदेखी की है, बल्कि अपने ही नेताओं के क्षेत्रों को भी राहत देने में असफल रही है। ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और उनकी यह मजबूरी सरकार की उदासीनता का जीता-जागता सबूत है।

